मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे।

सभी कार्यकर्ता निकाय व पंचायतीराज चुनावों की तैयारी करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर व भरतपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काम करें।**
- **बैठक में मुख्यमंत्री के साथ भरत राठौड़, प्रेम चन्द बैरवा, अरूण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, अशोक परनामी व राजेन्द्र राठौड़ भी शामिल हुए।**

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन से लेकर समाज व देश की सेवा में तत्पर रहता है, जिससे वह सदैव आगे बढ़ता है तथा सम्मान भी प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पार्टी का कार्य सर्वोपरि है, इसलिए दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं तथा मंडल स्तर की नियमित बैठकें भी करें। उन्होंने कहा कि मेहनती कार्यकर्ता और पदाधिकारी राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और 2 वर्षों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन तक पहुंचाएं। वे पार्टी की रीति और नीति को भी हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ-साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य करें। संगठन में युवाओं को केन्द्र व राज्य के कार्यक्रमों से जोड़ें और उन्हें जिम्मेदारी भी दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भेद-भाव और तुष्टीकरण के आधार पर वार्डों और पंचायतों को जोड़ा और तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने तथ्यों और आवश्यकता को देखते हुए पुनर्गठन के कार्य को पूरा किया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता आने वाले निकाय और पंचायतीराज चुनाव की तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नए लोगों को पार्टी से जोड़ें तथा उन्हें जिम्मेदारी दें। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को काम के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने संविधान दिवस को एक उत्साहवर्धक अवसर बताया और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में बार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं को संवैधानिक आदर्शों के मशाल-वाहक बताते हुए कहा कि बार की गहरी विद्वत्ता संवैधानिक व्याख्या की नींव बनाती है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कानूनी दिग्गजों जैसे नानी पालकीवाला, एम.सी. सीतलवाड, संविधान निर्माताओं डॉ. बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के योगदान को याद किया और कहा कि भारत की कानूनी यात्रा उन अधिवक्ताओं द्वारा आकार दी गई है जिनकी बुद्धि और ईमानदारी ने राष्ट्र के विकास का मार्गदर्शन किया।

सीबीआई ने आईटीएटी सदस्य, एडवोकेट व अपीलकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

सीबीआई के छापों में एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है

- **आयकर अपील ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य डॉ. सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। सीबीआई ने जाँच का दायरा बढ़ाकर जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे।**

जयपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की न्यायिक सदस्य, एक वरिष्ठ वकील को गिरफ्तार किया है। अधिकरण में अपील करने वाले शख्स को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उस आपराधिक नेटवर्क पर की गई है जो कथित तौर पर लंबित टैक्स अपीलों को घूस लेकर सेट कर रहा था।

सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया,आईटीएटी की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीता लक्ष्मी, एक सहायक रजिस्ट्रार और अन्य अज्ञात सरकारी व निजी व्यक्तियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है। यह पूरा गिरोह अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसले दिलवाने के लिए रिश्वत ले रहा था।

सीबीआई ने 25 नवंबर 2025 को इस संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही आईटीएटी के एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया को 5.50 लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत कथित तौर पर अपीलकर्ता ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से दी थी। इसी कड़ी में ऑपरेशन के अगले ही दिन बुधवार को आईटीएटी जयपुर की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीता लक्ष्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सरकारी कार से 30 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। रिश्वत देने वाले अपीलकर्ता मुजम्मल को भी बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की। जिसमें एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। जो इस खेल में संगठित सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस गिरोह में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। जो न्यायिक प्रक्रिया को पैसे के दम पर रौंदने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है।

दिल्ली विस्फोट : जांच एजेन्सियों ने डॉ. आदिल की डिलीट चैट वापस हासिल की

फोन संदेशों में आदिल बार-बार पैसों की मांग कर रहा है

- **सूत्रों के अनुसार 5,6,7, और 9 दिसम्बर 2025 के संदेशों में तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई गई। अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।**

नयी दिल्ली, 26 नवम्बर। दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें डॉ. आदिल के डिलीट किए गए व्हाटसअप चैट को दोबारा हासिल करने में सफलता मिल गयी है।

इस मामले में डा. आदिल एक मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पता चला है।

जांच एजेंसियों को दोबारा मिले इन संदेशों में उसकी आर्थिक तंगी की स्थिति स्पष्ट दिखती है। वह बार-बार पैसों की मांग करता दिखाई देता है। जांचकर्ताओं का संदेह है कि यही रकम उस हमले में इस्तेमाल हुई, जिसमें आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी ने अपनी आई20 कार में विस्फोट कर दिया था। इस हमले में पंद्रह लोगों की जान गयी थी और बत्तीस से अधिक लोग घायल हुए थे।

एक सूत्र ने बताया, आदिल के फोन से सभी संदेश मिटा दिए गए थे। इन संदेशों में वह लगातार पैसों की मांग करता दिखाई देता है। यहां तक कि उसने एक बार तो अपनी तनख्वाह तक एडवांस में मांगी।

संदेशों के जरिए हुई बातचीत 5, 6, 7 और 9 सितम्बर 2025 की हैं। इनमें उसने तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।

सूत्रों के अनुसार, कुल 26 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये आदिल ने उपलब्ध कराए थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि समूह में आदिल को खजांची कहा जाता था।

जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि डॉ. आदिल कथित घटनाओं से ठीक पहले श्रीनगर से 11 अक्टूबर को दिल्ली आया था।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। चार दिन तक चले इस हमले में 166 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस हमले में मुंबई के लग्जरी होटल, प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सांस्कृतिक केन्द्र को निशाना बनाया गया था। हमले के लिए आतंकवादी समुद्र के रास्ते आये थे। उन्होंने कई गुटों में बंटकर गाड़ियों पर कब्ज़ा किया। इसके बाद उन्होंने ताज महल पैलेस, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफ़े सहित, कई प्रमुख जगहों को निशाना बनाया।

कसाब को 2010 में मौत की सज़ा सुनायी गयी और 2012 में पुणे के एक कारागार में उसे फांसी दी गयी।

राबड़ी देवी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेजस्वी से उस बँगले को खाली करने के लिए कह दिया गया। तेजस्वी ने इस निर्णय/आदेश को अदालत में चुनौती दी, मगर 19 फरवरी 2019 के पटना हाई कोर्ट के फैसले में उनके खिलाफ निर्णय आया और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधाएँ वापस ले ली जायें। इस फैसले का असर राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्र पर भी पड़ा, लेकिन राबड़ी देवी के पास 10, सर्कुलर रोड वाला बँगला इसलिए बना रहा, क्योंकि वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं। आज भी वे उसी पद पर हैं, लेकिन नई सरकार का अब इस बँगले को लेकर अलग रुख है। यह बँगला प्रकरण इस बात का संकेत है कि नई नीतीश सरकार लालू परिवार से जुड़े लंबित केसों में नरमी नहीं बरतेगी।

'जब अलावेरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेनी चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

आलावेरू और उनकी टीम का कहना है कि वे अगले चुनाव के लिए नई पीढ़ी की टीम तैयार कर रहे थे, जो आगामी चुनाव में दिखेगी। लेकिन इस लाइन को कुछ ही लोग मान रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के पास उनके कामकाजी तरीके के खिलाफ शिकायतों की लम्बी लिस्ट है। एक और गुट का कहना है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, तो उसे राजद (आरजेडी) के सहारे को छोड़कर अपनी मजबूती से खुद खड़ा होना होगा और खुद को फिर से बनाना होगा।आरजेडी के खिलाफ भी कई गंभीर शिकायतें हैं, जैसे कि कांग्रेस को हारने वाली सीटें दी गईं और पार्टी को हराने के लिए विभिन्न चालें चलीं गईं। साथ ही, दोस्ताना मुकाबलों में कांग्रेस ने बुरी तरह से खराब प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जमानत गंवाई, जहाँ वह आरजेडी के साथ दोस्ताना मुकाबले में थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन वहाँ हार गया।

अगर पार्टी के नेता खुले तौर पर और ईमानदारी से बोलते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की जाती, तो पार्टी को इससे फायदा हो सकता है।

नहीं तो पार्टी के लिए समस्याओं का अंबार लग सकता है।

मुंबई की मतदाता सूचि में बड़ी अनियमितताएं सामने आईं

मुंबई, 26 नवम्बर। मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ सामने आने के बाद, प्रशासन ने इन्हें ठीक करने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत मतदाता सूची में नामों के दो-दो बार दर्ज होने की सामने आई है। इन डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करना

- **प्रशासन मुंबई के नगर निकाय चुनावों से पहले इन कमियों को दूर करने में जुटा है**

और उनको सूची से हटाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए पांच दिसंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को ठीक करना और गलत एंट्री हटाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्वीकार किया कि बृहन्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने डुप्लीकेट नामों का मुद्दा उठाया और इसे "गंभीर मामला" बताते हुए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे ने मुंबई में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, मनसे, राकांपा (शरद पवार), कांग्रेस, किसान-कामगार पार्टी, वाम दलों तथा अन्य विपक्षी समूहों ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर और "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए शहर में टुथ मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने धारावी की मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

भारतीय संविधान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को उनकी अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने और समझने का मौका है। आप अपने संविधान को अपनी भाषा में पढ़ सकते है। सरकार ने 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं में अनुवाद कराया है- नेपाली, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओड़िया, असमिया। इन अनुवादों को केन्द्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने तैयार किया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि नेपाली भाषा में संविधान का उपलब्ध होना है। यह कदम भारत और नेपाल के बीच के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों को देखते हुए काफी अहम है। नेपाली भाषी नागरिक अब अपनी भाषा में भारतीय संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव और मजबूत होगा।

विद्याधर नगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया, खो-नागोरियान सहित, जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले कुछ महीनों से लैपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आबादी क्षेत्र और हाई-सिक्यूरिटी ज़ोन में लैपर्ड का मूवमेंट वन विभाग और पुलिस दोनों के लिए चुनौती बन गया है।

'बाहरी बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी'

आईएमएफ ने भारतीय आर्थिक वृद्धि की तारीफ की और अनुशासन बनाये रखने की सलाह दी

- **आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाये गये 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ने के कारण कम होगा।**

वाशिंगटन, 26 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक बार फिर भारत की आर्थिक वृद्धि की तारीफ करते हुए बुधवार को कहा कि बाहरी बाधाओं के बावजूद यह मजबूत बनी रहेगी, हालांकि उसने करों में कटौती को लेकर वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की भी सलाह दी है।

आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के भारतीय अधिकारियों के साथ मशविरे के बाद जारी स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8 प्रतिशत रही है। उसने कहा कि खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम होने से मुद्रास्फीति की दर में भारी गिरावट आयी है। वित्तीय और कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूत बने हुए हैं, वित्तीय अनुशासन बेहतर हुआ है और चालू खाते का घाटा कम हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी बाधाओं के बावजूद, अनुकूल घरेलू कारकों की वजह से वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी और अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ने की वजह से कम होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालांकि कटौती और आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के मद्देनजर आईएमएफ ने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की जरूरत पर बल दिया है।

कार्यकारी निदेशकों ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर जीएसटी और व्यक्तिगत आयकर में कटौती के प्रभाव पर नजदीकी नजर रखने की सलाह दी है।

उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी आयात शुल्क के मद्देनजर निर्यातकों को दी गयी राहत लक्षित, पारदर्शी और सीमित समय के लिए होनी चाहिये। मध्यम अवधि में उन्होंने घरेलू राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में उच्च विकास संभावना वाले वृहत ढांचागत सुधारों को बढ़ावा देना मददगार हो सकता है।

ट्रंप की लाज बचाने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। प्रस्तावित समझौते की पूरी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं और सबसे अहम बात, रूस ने सार्वजनिक रुप से अभी तक किसी फ्रेमवर्क को मंजूरी नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सतर्क बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिकी पहल को स्वीकार तो किया लेकिन रूस की स्थिति स्पष्ट नहीं की, यह बात हालात की नज़ाकत को स्पष्ट करती है। अगर रूस ने खुलकर सहमति नहीं दी, तो ट्रम्प पर अधूरी कूटनीति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लग सकता है। ऐसी स्थिति उनके लिए उल्टी भी पड़ सकती है और आलोचनाएं और तेज़ हो सकती हैं।

फिर भी, ट्रम्प प्रशासन को विश्वास है कि बातचीत में बनी गति घरेलू राजनीति की धार बदल सकती है। खबर है कि अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल रूस के अधिकारियों से अबू धाबी में बातचीत कर रहे हैं, ताकि मॉस्को की सहमति सुनिश्चित की जा सके। वाइट हाउस भी संकेत दे रहा है कि ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। अगर ट्रम्प खुद को इस शांति प्रयास का सूत्रधार साबित कर पाए, या कम से कम वे ऐसे राष्ट्रपति साबित हुये, जिन्होंने सभी पक्षों को फिर से बातचीत की मेज़ पर बैठाया, तो इससे विरोधियों की आलोचना कम हो सकती है और हाल के हफ्तों में कमजोर हुई उनकी राजनीतिक स्थिति फिर मज़बूत हो सकती है।

डेमोक्रेट अभी भी सावधान और संदेहपूर्ण हैं। उनका कहना है कि इस प्रशासन के कई विदेश नीति प्रयासों ने बड़े-बड़े दावे तो किए, लेकिन स्थायी परिणाम नहीं दिए। यूरोपीय सहयोगियों को भी चिंता है कि अमेरिका तेज़ प्रगति के चक्कर में दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थिरता की उपेक्षा कर रहा है। हालांकि आलोचक भी मानते हैं कि यदि शांति समझौता वास्तव में सफल होता है, तो इसका राजनीतिक प्रभाव बेहद बड़ा होगा।

फिलहाल, अभी तो ट्रम्प की प्रैसिडैंसी की कमज़ोरियाँ साफ दिखाई दे रही हैं, गिरते सर्वेक्षण, कांग्रेस की बेचैनी और जनता की बढ़ती नाखुशी। लेकिन यूक्रेन शांति पहल ने महीनों बाद उन्हें पहला मजबूत मौका दिया है, जिससे उन्हें अपनी नेतृत्व छवि को दोबारा गढ़ने का एक मौका मिल सकता है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और रूस भी इसमें शामिल होता है, तो राष्ट्रपति ट्रम्प फिर से राजनीतिक गति पा सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत अटक गई, तो उनकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर उनकी राजनीतिक मुश्किलों को और बढ़ा सकता है।

आने वाले कुछ सप्ताह, पूर्वी यूरोप में भी और अमेरिकी राजनीति में भी, तय करेंगे कि ट्रम्प की यह शांति पहल एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनती है या एक और ऐसी खबर, जो उनके डगमगाते कार्यकाल में थोड़ी देर चर्चा के बाद गायब हो जाती है।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी इस आत्मघाती धमाके के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है। इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए संबंधित पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में एनआईए अधिकारी तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साज़िश का पता लगाने की एनआईए कोशिशें जारी हैं।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि यह गतिरोध जारी रहता है, तो स्पीकर का चुनाव, जो सामान्यत: एक रूटीन प्रक्रिया होती है, नई सरकार के लिए पहला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल, सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों गठबंधन पार्टियां 1 दिसम्बर को विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस बढ़ती जा रही दरार को पाटने में सफल हो पाएंगी।

'अनियंत्रित ऑन लाइन गेमिंग ऐप आतंकवाद को फंड करते हैं'

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा किया

- **हलफनामे में भी यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों, सैलिब्रिटी और सोशल इन्फ्लुएंसर के प्रचार से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म युवाओं और कमजोर तबकों में तेजी से फैल रहा है।**

नई दिल्ला, 26 नवम्बर। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना नियमन वाले ऑनलाइन गेमिंग एप्स का संबंध आतंकवाद को वित्तीय मदद देने और धन शोधन से जुड़ा है। इसलिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना जरूरी था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वे इस मामले की कल यानी गुरुवार को सुनवाई करने का प्रयास करेंगे।

सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि बिना रोक-टोक के बढ़ रहे ऑनलाइन जुए वाले गेम्स का संबंध वित्तीय धोखाधड़ी, धनशोधन, कर (टैक्स) चोरी और कई मामलों में आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने से भी जुड़ा है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रचार से युवाओं और कमजोर तबकों तक तेजी से पहुंच रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन जुए वाले गेम्स का व्यक्तियों, परिवारों, समाज और पूरे देश पर बुरा असर पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, एल्गोरिदम और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जैसे तकनीकी पहलुओं के चलते, ये कंपनियां विदेशों से संचालित होती हैं, घरेलू और राज्य स्तर के कानूनों को नजरअंदाज करती हैं और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से 2025 का ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन कानून बनाया गया।

सरकार ने कहा कि जनता की भलाई के लिए यह जरूरी था कि केन्द्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ले और एक सुरक्षित, व्यवस्थित और नवाचार को बढ़ावा देने वाला डिजिटल माहौल तैयार करे।

'कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले हैं। यह सत्ता-संघर्ष कर्नाटक इकाई में गुटबाजी की गहरी जड़ों को उजागर करता है, जहां एक समूह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन कर रहा है और दूसरा डीकेएस को सत्ता सौंपने की मांग करता है।

आज दोपहर की यह स्वीकारोक्ति पिछले हफ्ते की उस टिप्पणी से एक यू-टर्न भी है, जिसमें पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने, जून की तरह ही, यह कहा था कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908